

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
15.12.2021 के  
तारांकित प्रश्न सं. 241 का उत्तर

बैरबी-सायरंग रेल लाइन

\*241. श्री सी. लालरोसांगा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे (एनएफआर) के अंतर्गत बैरबी-सायरंग के बीच रेल लाइन के निर्माण कार्य को पूरा किए जाने की लक्षित तारीख क्या है;
- (ख) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है और इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय किया गया है;
- (ग) निर्माणाधीन रेल लाइन की लंबाई कितनी है और बनाए जाने वाले पुलों, टनलों और स्टेशनों की संख्या के संबंध में ब्यौरा क्या है;
- (घ) और रोजगार सृजन, यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई के संदर्भ में स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

भैराबी-सारंग रेल लाइन के संबंध में दिनांक 15.12.2021 को लोक सभा में श्री सी. लालरोसांगा के तारांकित प्रश्न सं. 241 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय रेल द्वारा भैराबी-सारंग (51.38 कि.मी.) नई लाइन परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना की प्रत्याशित लागत 6527 करोड़ रु. है। अभी तक इस परियोजना पर 4343 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 हेतु 1038 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

51.38 कि.मी. लंबी रेल लाइन निर्माणाधीन है। इस परियोजना में 55 बड़े पुलों का निर्माण शामिल है जिनकी कुल लंबाई 10.68 कि.मी. है, 87 छोटे पुल, 12.65 कि.मी. कुल लंबाई की 32 सुरंगें और 5 स्टेशन इमारतें शामिल हैं। इसमें प्रस्तावित स्टेशन भैराबी (मौजूदा), होरटोकी, कानपुई, मौलखंग और सारंग - टर्मिनल स्टेशन हैं।

रेल परियोजना का समय पर पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियों, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति इत्यादि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अतः परियोजना का निश्चित समापन समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथापि, परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं।

यह एक राष्ट्रीय परियोजना है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलग-थलग हिस्सों में कनेक्टिविटी में सुधार लाना भारत सरकार की नीतिपरक पहल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशाल स्तर पर चल रहे क्रियाकलापों के कारण रोजगार सृजन की संभावनाएं पहले ही बढ़ी हुई हैं। देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी में सुधार होने के परिणामस्वरूप क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा।

\*\*\*\*\*